

न्यायालय जिला कलक्टर, पाली  
पीठासीन अधिकारी : श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस.

राजस्व विविध प्रकरण संख्या : 83/2021  
जी.सी.एम.एस. संख्या : 2021/267

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. वेनाराम पुत्र श्री पोकर, जाति गाडोलिया लोहार, निवासी बिदू तहसील रोहट जिला पाली		1. मृतक देदा पुत्र तेजाजी 1/1. सुरेश पुत्र श्री देदाराम 1/2. पमीया पुत्र श्री देदाराम, जाति पटेल निवासी बिदू, तहसील रोहट जिला पाली।
2. राजूराम पुत्र श्री मदनलाल, जाति गाडोलिया लोहार निवासी बिदु रोहट जिला पाली।		1/3. सुमित्रा पुत्री देदाराम 1/4. गोपी पुत्री देदाराम 1/5. सारकी पत्नी ददाराम जातिगण पटेल निवासीगण बिदू, तहसील रोहट जिला पाली।
		2. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, रोहट

राजस्व विविध प्रार्थना पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4)

उपस्थित :-

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत सिंह राजपुरोहित  
अप्रार्थी संख्या 1/1 से 1/5 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना  
-: निर्णय :-

दिनांक :- 20.01.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत तहसीलदार रोहट द्वारा ग्राम बिदु के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा में आवंटन आदेश 01.07.1965 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। जैर आवंटन आदेश तलब किया गया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मतसिंह राजपुरोहित अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाना उपस्थित हुए। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

प्रकरण के संबंध में संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 देदा पुत्र तेजा जाति पटेल के नाम ग्राम बिदु के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा भू-आवंटन किया गया है। उक्त आवंटन में हल्का पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 भूमिहीन है जबकी इस भूमि पर प्रार्थी व प्रार्थी के भतीज को मौके पर सामूहिक तौर पर कब्जा काशत है, इसलिये कब्जे की भूमि को जो भू आवंटन किया है जो विधि विधान के प्रतिकूल है और इस पर प्रार्थी व प्रार्थी के भतीज का कब्जाकाशत होने से व साथ ही प्रार्थीगण भूमिहीन है ऐसी सूरत में प्रथम तो धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत बेदखली करनी थी और इस तरह का नोटिस देकर अधिपत्य विहिन करके ही भू आवंटन किया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया, वैसे प्रार्थीगण भी इस भूमि पर कब्जे में थे तो नियमों के तहत प्रार्थीगण के कब्जे को विनियमित किया जाना चाहिये थे, जो नहीं किया है, इस कारण भी ऐसा भू आवंटन खारिज योग्य है। जैर आवंटन होने के पश्चात् भी आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना भी नहीं की गई। जैर आवंटन के समय आवंटी भूमिहीन नहीं था व आवंटी के नाम वक्त आवंटन उसके पूर्वजों से प्राप्त जमीन होने से उक्त जमीन में आवंटी का नोशनल शेयर होते हुये भी जैर



जिला कलक्टर, पाली



2. द्वितीयतः आवेदक द्वारा उक्त भूमि पर अपना कब्जा होना अवगत करवाया है, जिस बाबत विपक्षी ने अपने पक्ष में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मणीराम बनाम देवीसिंह आर.बी.जे. 2009 (16) पेज संख्या 789 न्यायिक नजीर प्रस्तुत की जिसमें सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि **when disputed land was in possession of the appellatant as trespasser – Such possession would be considered as trespass – a trespassed land is not considered as an occupied land and such land is available for allotment** अर्थात् अन्य व्यक्ति का कब्जा trespass ही माना जाता है तथा उसका कोई locus standai नहीं होता।
3. प्रार्थी आवेदक का तृतीय उज्र आवंटन बाबत आवेदन प्रस्तुत नहीं होना, उद्घोषणा नहीं होना तथा अधिपत्य विहिन भूमि की कोई सूची तैयार नहीं होना परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने उक्त उज्र के समर्थन में भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है, जिससे प्रार्थी आवेदक का उक्त कथन भी माना जाने का कोई विधिक आधार नहीं है तथा आवेदक द्वारा इस हेतु कोई नकले मांगी गई हो तथा सक्षम अधिकारी द्वारा इस बाबत कोई विधिक पूर्ति नहीं की गई हो, ऐसा कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। आवंटन के पक्ष में किये गये आवंटन के समय अपनाई गई प्रक्रिया में कोरम अपूर्ण होने से संबंधित होने के कथन के समर्थन में भी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं।

इसके अतिरिक्त 56 वर्ष पूर्व किये गये आवंटन में आवंटन शर्तों की पालना नहीं होना माना जाना एवं विशेष रूप से तब जब सक्षम अधिकारी द्वारा आवंटन को खातेदारी अधिकार प्रदान कर दिये हो, कोई विधिक आधार नहीं है। आवेदक का यह कथन कि जैर आराजी पर उसका पश्चातवृत्ति नाम दर्ज हुआ है परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन भी समायपयोगी नहीं है क्योंकि जैर आवंटन विधिवत होना ही प्रमाणित है।

समग्र रूप से हम लगभग 56 वर्षों बाद सरसरी, अत्यन्त तकनीकी एवं सारहीन आधारों पर आवेदक द्वारा वर्णित आधारों पर जैर आवंटन को खारिज किये जाने के कोई विधिक एवं तथ्यात्मक आधार नहीं पाते हैं। अतएव प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत राजस्थान कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(4) अविधिक एवं सारहीन होने से खारिज कर अप्रार्थी के पूर्वज देदाजी के पक्ष में ग्राम बिटू के खसरा संख्या 499 रकबा 15 बीघा के किये गये आवंटन आदेश दिनांक 01.07.1965 को बहाल रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.01.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)

जिला कलक्टर, पाली  
जिला कलक्टर, पाली

